ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **10 March, 2021**

Shri Mallikarjun Kharge, Shri Anand Sharma, Shri Akhilesh P Singh, Shri Deepender Hooda and Shri Nasir Hussain addressed the media at AICC Hdqrs, today.

श्री नसीर हुसैन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज की इस प्रेस वार्ता में आप तमाम लोगों का स्वागत है। पिछले तीन दिन से जिस तरह लोकसभा, राज्यसभा में फ्यूल हाईक को लेकर, कृषि कानून को लेकर, फार्मर एजिटेशन को लेकर मुद्दे उठाए गए और तीन दिन से लगातार लोकसभा, राज्यसभा स्थगित की गई है,-लगातार अडर्जमेंट होते रहे हैं, इस चीज को लेकर आपके सामने अपनी बात रखने के लिए, हमारे बीच में आप लोगों के समक्ष आज श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो एलओपी हैं राज्यसभा में। इन्हीं के साथ में हमारे डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा, श्री आनंद शर्मा जी, वरिष्ठ नेता, फार्मर यूनियन मिनिस्टर, श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, श्री प्रणव जी, श्री संजीव जी हमारे बीच में हैं। इसी के साथ में राज्यसभा मैंबर दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और प्रणव जी, एआईसीसी सेक्रेटरी, संजीव सिंह जी मीडिया कॉर्डिनेटर हैं। हम तमाम लोग आपके सामने पिछले तीन दिन में क्या हुआ, किस तरह से सरकार बात नहीं करना चाह रही है और बात करने देना नहीं चाह रही है और किसी भी बहस के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही है। इस चीज के लिए आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो एलओपी हैं राज्यसभा में, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मंच पर बैठे हुए, हमारे डिप्टी लीडर, आनंद शर्मा जी और अखिलेश जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, नसीर साहब और आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। अभी जो नसीर हुसैन जी ने जो कहा, सदन में हम किस ढंग से तीन दिन से लगातार पेट्रोल-डीजल, एलपीजी, केरोसिन, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन वस्तुओं की जो कीमत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार ने उनकी कीमतों को घटाने की कोई कोशिश नहीं की और एक्साइज ड्यूटी इन चीजों पर उन्होंने ज्यादा लगाते हुए सबसे महंगा, भारत के इतिहास में इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं हुआ और डीजल, वो भी नहीं था। केरोसिन जैसा पीडीएस में गरीब लोगों को दिया जाता है, उसकी भी कीमतें आसमान पर चढ़ी हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में थी, राज्यसभा में थी। हमने बहुत कोशिश की, रुल 267 के तहत इस विषय को उठाकर सदन में डिटेल में चर्चा करना चाहते थे। लेकिन सरकार ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें मौका नहीं दिया।

इन चीजों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने इस 6-7 साल में 21 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। हम सरकार ये यही पूछना चाहते थे कि उस 21 लाख करोड़ में कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं, किन-किन चीजों पर आपने खर्च किया? किन योजनाओं पर आपने इस पैसे को लगाया? ऐसे हमारे बहुत से सवाल थे, जो कि समय की कमी के कारण आपके सामने नहीं रख सकता। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर जो पैसा उनको मिला, इसका हिसाब हम लेना चाहते थे। लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया। हम दो दिन से लड़ते रहे और आज तीसरा दिन है।

आप सभी को मालूम है कि यूपीए के समय में जब क्रूड 109 डॉलर पर बैरल था, कभी-कभी वो 140 तक चला गया, इसके बावजूद भी हमनें 71 रुपए से ज्यादा पेट्रोल लोगों को नहीं दिया। उसी कीमत पर रखा, क्योंकि जनता की जो तकलीफें थी, जो कष्ट थे, उसको हम जानते थे। और डीजल की कीमतें भी हमने बहुत कम रखी, 30-34 रुपए तक। केरोसिन 14 रुपए था हमारे जमाने में। आज वो 35 रुपए हो गया है। उन्होंने उज्जवला स्कीम की घोषणा करके, उसका प्रचार ऐसा किया कि मोदी जी मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं। जब एलपीजी का सिलेंडर देने की योजना बनी तो हर जगह सिलेंडर के साथ फोटो। पेट्रोल पंप पर फोटो, हर जगह पब्लिसिटी लेने के लिए ये काम करते हैं। आजकल कोविड की जो वैक्सीन दे रहे हैं, उसके ऊपर भी उनकी फोटो। तो कहना मतलब एक हद होती है, किसी चीज का कहाँ पर इस्तेमाल आप करें, कहाँ पर नहीं। ठीक है, आप पैसे देते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज पेपर में आता है, टीवी में आती है, वो बात और है, लेकिन हर चीज पर एक व्यक्ति अपने प्रचार के लिए अगर ऐसा करते गए, तो क्या देश में लोकतंत्र बचेगा? और लोकतंत्र को बचाने के लिए जब आपके नागरिक सुखी और संपन्न हों, तभी यह बचता है। एक तरफ तो हमें कहते हैं कि संविधान के तहत चलना चाहिए, संविधान के अनुसार हमें काम करना चाहिए, लेकिन संविधान की धज्जियाँ आज खुदउड़ा रहे हैं। संविधान के तहत ही हमने रुल 267 में ये चर्चा की मांग की थी, बिजनेस ट्रांजेक्शन रुल के मुताबिक हम उस मुद्दे को उठा रहे थे। लेकिन वो उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं।

तो ये है कि गरीबों को जो आज मार पड़ी हैं और मिडिल क्लॉस के, मध्यम वर्ग के लोगों को भी मार गिराया है पेट्रोल से और जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जो हमेशा लाइन में खड़े होकर राशन लेते हैं और केरोसिन भी लेते हैं, उनको मार गिराया है। और एलपीजी जो हमारी माताएं, पहले बहुत खुश थी, थोड़े जो गरीबी में रहने वाले, हमें ग्लास मिला, फ्री में ये दिया, आज उसकी कीमत बढ़कर 565 रुपए हो गई हैं और नोन सब्सिडी का 890 रुपए का हो गया है, यानि हर चीज में, एक तरफ तो महंगाई की मार, इसके अलावा ये और इसका इफेक्ट किसानों पर पड़ा, क्योंकि किसान डीजल इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टर में इस्तेमाल करता है, टेलर में यूज करता है, क्रोप हार्वेस्टिंग में इस्तेमाल करता है, उसको भी मार और सभी को मार। मार पर मार करके आज पहले ही कोविड़ इसकी परिस्थिति में हमारी आर्थिक स्थिति खत्म हो चुकी है और बर्बाद हो चुकी है। इसके बावजूद भी

मोदी साहब समझ नहीं पाते हैं कि वो हमेशा वो जो कहते हैं, वही सच है, उनका मानना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, देश की आर्थिक परिस्थिति को और भी दुर्बल बनाने का काम उन्होंने किया। चाहे ये डीजल-पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी का हो, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे बिना सोचे-समझे लॉकडाउन करने का हो। करोडों माइग्रेंट वर्कर, लाखों बच्चे रास्ते पर आए। तो ऐसे काम करके उन्होंने इस देश की जनता को गरीबी से मुक्त करने की बजाए और उनको गरीबी के पिंजरे में धकेल दिया है और गरीब-गरीब बन रहा है, अमीर-अमीर बन रहा है और चंद मालदार लोग, कॉर्पोरेट कंपनी, वो खुश हैं। क्योंकि वो लिमिटेड़ लोगों की मदद करके, उनको खुश रखना चाहते हैं। अरे, कॉर्पोरेट कंपनी के टैक्स आप कम करते हैं और इधर छोटे लोग जो इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों की कीमतें आप बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को सामने रखने के लिए ही दो दिन से हमने पार्लियामेंट में इसके बारे में बहुत कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि सरकार इसको कॉपरेट नहीं करना चाहती, वो परेशान करना चाहते थे। इसलिए आगे जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बारे में डिटेल में हमारे दूसरे नेता बताएंगे। आपको मैं धन्यवाद देता हूं और एक बात कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं।

अब कोई और ना धोखा देगा, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे। हमसे हर ख्वाब छिनने वाले, हमारी नींद तो वापस कर दे।

तो ये मोदी जी के लिए कह रहा हूँ, सबको परेशान कर रहे हैं, कोई नींद नहीं ले रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि खाना तो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए उनसे कहूंगा कि उनकी सरकार के लिए ये ठीक समझ कर मैं यहाँ कह रहा हूं और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आगे की कार्यवाही चलाईए।

श्री आनंद शर्मा ने कहा कि, खड़गे जी ने अभी क्या विषय उठाए हैं, विपक्ष की तरफ से, उसका ब्योरा दिया। संसद सबसे ऊंचा स्थल है, मंच है, भारतीय प्रजातंत्र का, यहाँ केवल सत्ता पक्ष नहीं, सरकार की बात नहीं, पर जनता की आवाज रखना विपक्ष का- प्रतिपक्ष का अधिकार और कर्तव्य होता है। संसद नियमों पर चलती है और देश संविधान पर। नियमों के तहत जो चर्चा की मांग की गई, ज्वलंत समस्याएं जो जनता के सामने हैं, जिस तरह महंगाई की मार है, सरकार की मुनाफाखोरी है। पिछले साढ़े 6 साल से, सातवां साल खत्म होने वाला है, जहाँ छोड़ कर गए थे, जैसा खड़गे जी ने बताया 109, 112 डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमत थी मई 2014 में दिल्ली में 67 रुपए एक लीटर पेट्रोल था और डीजल 58 रुपए था, आपको याद होगा। उसके बाद पिछले 6 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत टूटी है और लगभग औसतन, एवरेज 40 डॉलर के आस-पास क्रूड पेट्रोलियम की कीमत रही है। जब यूपीए की सरकार थी, 290 बिलियन डॉलर क्रूड पेट्रोलियम का इम्पोर्ट था। तो यहाँ पर जो पैसा बचा है, उसमें जनता को राहत देने की जगह सरकार उसको दूसरी तरफ इस्तेमाल कर रही हैं, निरंतर ड्यूटी बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है।

So, this Government is guilty of monumental mismanagement of the Indian economy. It is not allowing a normal functioning of the highest institution of India democracy. The opposition is being deprived and denied continuously their right to raise issues, which matter to the people of India, without going into the details, what has been referred to by the Leader of Opposition, Kharge Ji and what I briefly alluded to that the Government has questions to answers and we have a right to ask those questions.

In the first half of the budget session, we were not allowed to raise issues. There is a complete negation of Parliamentary practice as well as presidents where the opposition is allowed to raise discussion on at least one matter of public importance every week. Convening of Parliament is not meant only for the transaction of the Government businesses, but, notices are given under rules, the rules have to be respected. We respect the rules, and under the rules the notices are given. The Government also ought to respect that and whether in Rajya Sabha or in Lok Sabha, the opposite must be given us space and voice. Continuation of this practice is hitting at the very route of Indian democracy, which will be resisted and opposed by us.

Other issue is about the farmers, for last 104 days, hundreds of farmers have died. Sometimes in Politics and in the politics discourse, it is important to remind, how those bills were passed in violation of the Constitution, Parliamentary rules, practices and established precedence. Opposition was not allowed to speak. The demand for a division and the vote was not allowed. We had suggested then to the Government that they should allow the opposition demand and accept to refer the bill to a standing committee, had that been accepted- had the legislative scrutiny taken place, the country would not have seen the suffering of the farmers and their agitation.

I would only say that still sometime is left for whatever is the remaining days of the budget session before it concludes, the Government must change the attitude and the country must hear their representatives, who are elected representatives representing the opposition parties to raise issues, so that the people can be reassured that Indian democracy is functioning and the people's issues are being agitated in the right forum.

श्री अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी लीडर आनंद शर्मा जी ने विस्तार से जो कुछ पिछले 3 दिन में राज्यसभा - लोकसभा में हुआ है, उसकी चर्चा की है। मैं केवल इतना ही जोड़ना चाहता हूं, मैं बिहार से आता हूं और मैं जहाँ से लोकसभा में काम करता था, चंपारण का इलाका, उस इलाके में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल से सटा हुआ। नेपाल में कीमत अभी भी 25 से 30 रुपए प्रति लीटर भारत से कम है। मैं एक श्राद्ध क्रम में गया हुआ था और देखा कि बड़ी संख्या में नौजवान वहाँ से पेट्रोल और डीजल भर-भर कर इस तरफ ला रहे हैं। मैंने जब उन लोगों से पूछा, तो बोले की काम करने के लिए तो कुछ है बिहार में। तो इससे कम से कम 2,4 हजार रुपए बच जाते हैं। दिनभर हम ये काम उधर से इधर लाकर करते हैं। सरकार को जांच करनी

चाहिए कि आज क्या स्थिति है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उस समय यूपीए के जमाने में 109 डॉलर प्रति बैरल था और आज 65 आ गया है नीचे, उसके बावजूद और यही मोदी जी, बीजेपी के साथी लोग कहा करते थे कि 70 रुपए से ज्यादा पेट्रोल कैसे बिक सकता है इस देश में और आज वो 100 रुपए पहुंच गया? डीजल की कीमत 80 रुपए पहुंच गई। गरीबों के थाल से दाल और सब्जी गायब है। ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना पर कोई संविधान और शासन चलाने वाला देश इस पर चर्चा कराने को तैयार नहीं।

3 दिन से लगातार आवाज उठ रही है, प्रतिपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। 300 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, फिर भी मोदी जी में संवेदना नहीं जगी और केवल यही नहीं, पूरे देश में किसानों के समर्थन में किसान खड़े हैं, भले ही वो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जहाँ हैं और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है और ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें भी मोदी जी को निश्चित रुप से पता चलेगा कि उनकी लोकप्रियता का ग्राफ, जिसका वो दावा करते हैं, वो कितना नीचे गया है।

श्री दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दो मुख्य मुद्दों को लेकर हमने इस हफ्ते में तीनों दिन सरकार से आग्रह किया कि उस पर बातचीत हो। मैं जो दूसरा मुद्दा है, कृषि का, किसानों के आंदोलन का, उसके बारे में मैं दो मिनट आपसे कुछ बात साझा करना चाहता हूं।

हमने ये क्यों रखा, रुल 267 जो राज्यसभा का है, उसमें है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है देश के सामने, जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा करने जा रही है, उनका बिजनेस है, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो उसको सस्पेंड करके, सारे बिजनेस को सस्पेंड करके उस पर चर्चा ली जा सकती है। जो आज लिस्टेड था राज्यसभा में, वो तोमर जी का ही, एक रविशंकर प्रसाद जी का बिजनेस लिस्टेड़ था, एक तोमर साहब का बिजनेस लिस्टेड था कि जो 'निफटेम' कांग्रेस की सरकार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनजमेंट, उसको के इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना । वहीं सिंघु बॉर्डर पर, उसका तो आज आपने लिस्ट कर दिया, उसी सिंघु बॉर्डर पर कल तीन किसानों की, जिसमें एक महिला किसान भी थी, कल की बात है और ये पिछले 105 दिन से लगातार वो तो आपको दिख रहा है निफटेम, लेकिन वो जो 120 किलोमीटर लंबा धरना, जबाँ हजार-लाखों की तादात में किसान बैठे हैं। महिलाएं, बच्चे, वो आपको नहीं दिख रहे।

प्रेस वालों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी सरकार से पूछना चाहती है कि क्या आजाद भारत के इतिहास में, देशवासियों ने अपने जीवन काल में कोई ऐसा आंदोलन देखा, जिसमें 300 जानें कुर्बान हो गई हों? 105 दिन जहाँ आंदोलनकारियों ने तमाम आरोप और तिरस्कार झेले हों! उनको हर प्रकार की बात कही गई हो, फिर भी आंदोलनकारी इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में और इस प्रजातंत्र के मंदिर संसद में, इस संसद पर आस लगाए धैर्य और संयम के साथ अभी भी लाखों की तादात में बैठे हैं!

कल रात को भी टिकरी बॉर्डर पर बारिश हुई, आंधी चली, सारे टैंट उखड़ गए। चौकी, खाना बनाने वाली चौकियां उखड़ गई, महिलाएं, 80-80 साल की महिलाएं। क्या हम- क्या संसद मूक दर्शक बनी रह सकती है? क्या आप लोग, मीडिया, आप चुप रह सकते हैं, जब देश में ये हो रहा हो? क्या सरकार इस संघर्षरत किसानों को उनके हाल पर छोड़कर अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाएगी? देश में 70 प्रतिशत नागरिक किसान परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो कृषि में नहीं भी हैं, लेकिन किसान परिवार की पृष्ठभूमि से 70 प्रतिशत नागरिक हैं। एक बार जरा इन संघर्षरत किसानों को अपना ही परिवार मान कर देखिए।

आप लोगों में से भी मैं बहुत लोगों को जानता हूं, जो किसान परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। सोचिए कि आपके ही पिता समान किसान, निर्दोष किसान को आतंकी कहा गया। सोचिए आपके ही भाई पर लाठियां और आंसू गैस के गोले दागे गए। सोचिए आपकी ही माताएं, बहनें दिल्ली की सीमा पर टैंटों में सोने को मजबूर हैं। 80-80 साल, 70-70 साल की महिलाएं, छोटे-छोटे बच्चे। हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कम से कम बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों की बददुआ ना लें।

जैसा अभी कहा अखिलेश जी ने कि दो दिन पहले किसान ने आत्मबलिदान किया और केवल किसान नहीं, संत से लेकर किसान तक, गरीब किसान तक, वहाँ पर लोगों ने आत्मबलिदान भी किया। उन्होंने जो अपने अंतिम शब्द लिखे। मैं वो नोट कोई पूरा आपके समक्ष नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक है। लेकिन उन अंतिम शब्दों में से एक वाक्य अधूरा मैं जरुर पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा राजबीर जी ने, सिसाए गांव के, कि "सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तो मेरी आखिरी इच्छा है कि तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई जाए और किसानों को आप खुशी-खुशी वापस भेज दें।" अभी भी आस है प्रजातंत्र की व्यवस्था में, इस संसद में और इस सरकार से, ये आखिरी शब्द लिखे थे। और यहाँ सरकार का क्या रवैया है, इन लोगों के प्रति सरकार ने संवेदना का एक शब्द या सहानुभूति का एक वाक्य इस संसद में सरकार के सबसे जूनियर मंत्री के मुख से भी देश ने सुना नहीं।

मैं पूछना चाहता हूं ये 300 लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं? जब देश के किसी कोने में या विदेश में भी कोई छोटी-मोटी घटना हो जाती है, तो प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्रियों के ट्विटर से लेकर बड़े बयान आते हैं, सहानुभूति के, संवेदना के, हम भी उनके शोक में शामिल होते हैं। ये 300 लोग कौन थे, आप इनके घर में जाकर देखिए? कांग्रेस पार्टी आप लोगों से आग्रह करना चाहती है, क्या इनके प्रति सहानुभूति नहीं व्यक्त करनी चाहिए? अब मैं आज वाले मुद्दे पर आकर अपनी बात समाप्त करता हूं। पहले सरकार ने इन आंदोलन संघर्षरत, आंदोलनकारियों को किसान मानने से इंकार किया। कहा कि ये आतंकवादी, अलगाववादी हैं। फिर इन किसानों को इंसान मानने से इंकार किया, सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं आए। इन किसानों को खारिज किया। इन किसानों की मांगों को खारिज किया, इन किसानों की कुर्बानियों को खारिज किया, जब हमने मांग की कि

इनके प्रति संवेदना व्यक्त की जाए, तो हमारी उस मांग को खारिज किया और अब आज हमने जब मांग की कि कम से कम इस पर चर्चा करा ली जाए, तो उस चर्चा की मांग को भी पूरी तरीके से खारिज करके सरकार किसान को उसके हाल पर छोड़कर चली गई।

तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों से ये आग्रह करता हूं कि इन किसानों के कुर्बानियों को लोकतंत्र में हमारी आवाज, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंच सकती है, तो उसमें आप सहायक साबित हों और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार का जो रवैया है किसान के प्रति, उससे आज देश के करोडों किसानों के दिलों में बहुत पीड़ा हुई।

श्री नसीर हुसैन ने कहा कि खड़गे साहब जी, आनंद शर्मा जी पिछले तीन दिन से सरकार से बहस की मांग कर रहे हैं पर वो चर्चा नहीं करवा रही है, आप लोगों को बताया है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। नोटबंदी, उसके बाद में सीएए, एनआरसी, उसके बाद दिल्ली के दंगे, उसके बाद गिरती हुई जीडीपी और गिरती हुई आर्थिक स्थिति पर, चीन इंट्रूयूजन पर, फिर उसके बाद में बजट सत्र के समय इसी किसान के मुद्दे पर कई बार हम लोगों ने प्रस्ताव रखा कि हम लोगों ने नोटिस दिया कि इसके ऊपर चर्चा हो और बहस हो, लेकिन बहस करने नहीं दी गई। बहस से ये भागते रहे। उन लोगों को मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो कह रहे हैं कि विपक्ष डिसरप्शन कर रही है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, दोनों ने भी कहा था 'Disruption is the right of opposition, Disruption has a place in Parliamentary practices', उन्होंने खुद ही कहा था। मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें सब्सिडी को लेकर, जीडीपी को लेकर मैं इतने ही आंकड़े देना चाहूंगा 2004 से 2009 तक यूपीए के राज में 67,451 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी। and 1,13,510 crore of subsidy was given petrol and diesel in from 2009 to 2014 अभी बीजेपी सरकार का सब्सिडी देने का, जो सब्सिडी दी, 2014 से 2019 के बीच उन्होंने सिर्फ 38 हजार करोड़ है और 2019 से 21 के अभी आंकड़े मौजूद नहीं है। अभी तक हमें पता चला है कि जीरो सब्सिडी दी गई है। तो इसमें बात ये है कि किस तरह से आप राहत दिला सकते हैं, ये बात सभी ने आपके सामने रखी हैं।

क्रूड ऑयल की कीमत पिछले 10 दिनों में बढ़ी है, लेकिन सरकार ने दाम नही बढ़ाए हैं, के उत्तर में श्री आन्नद शर्मा ने कहा कि जो आपने कहा ठीक है। पहले तो जैसा कहा था हमने पिछले सात सात मे औसत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 40 डॉलर के आस-पास रही है। जो कीमत है, ड्यूटीज और टैक्सेस हैं, वो उससे भी ज्यादा हैं, कई गुना जो पहले इस देश में कभी नहीं लगे, तब भी जबकि 109, 112, 140 डॉलर तक क्रूड का था। तो आज जो सरकार ने कीमत अभी बनाई है, वो तो डेढ सौ डॉलर या 175 डॉलर क्रूड की कीमत होनी चाहिए। 70 डॉलर नहीं, तभी आप आज की कीमत को उचित ठहरा सकते हैं। आज 70 डॉलर क्रूड हुआ है, लेकिन आंकड़े बताते हैं मुनाफाखोरी कर रही है। पर क्योंकि जनता में आक्रोश है, तो ये कोई राहत नहीं दी है, जो इतनी कमी आई बाजार में, कीमतें टूटी दुनिया में वो उपभोक्ता को, आप लोगों, आम गृहणियों को कोई राहत नहीं दी है, केवल वोट के लिए थोड़े दिन इस पर ब्रेक लगाया है, ताकि किसी तरह से लोग ये भूल जाएं कि कितनी तकलीफ दी है और इलेक्शन के बाद पूरा भरपूर तरीके से फिर से जनता पर थोप दिया जाएगा। सरकार जरा भी संवेदनशील नहीं है किसी भी विषय पर यही कहना चाहता हूँ।

On another question regarding opposing voices in the Party, Shri Anand Sharma said- Let me make one thing absolutely clear, Congress Party, historically has stood for internal discussion, issues are debated in the long history of Indian National Congress. If those who are aware during the freedom struggle, then Mahatma Gandhi was there, Pandit Jawahar Lal Nahru was there, Sardar Vallabb Bhai Patel, Subhash Bose, that tradition has continued in the Indian National Congress. There are no two groups in the Congress. It is one Indian National Congress. The President is Smt. Sonia Gandhi and right now the only objective before the Congress Party is, to fight these elections together to defeat the BJP, to defeat other opponents. But, let there be no wrong impression that the Congress Party will not fight these battles together.

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC